क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480 सह संपादक : संदीप मौर्या
E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 317, सोमवार, 17 दिसम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

न्यूज

कांग्रेस बनी दुश्मनों की मददगार : देव

अगरतला,(एजेंसी)। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने कहा है कि राफेल विमान खरीद मामले में दुष्प्रचार कर कांग्रेस और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी पर देश की सुरक्षा की कीमत पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं तथा उन्हें देश के लोगों से माफी मांगने जरूरत है। भाजपा त्रिपुरा के अध्यक्ष श्री देव ने शनिवार को कहा कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने भी राफेल सौदे मामले में स्पष्ट कर दिया कि इसमें किसी प्रकार का घोटाला या पक्षपात नहीं किया हुआ है बल्कि यह देश की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। श्री देव ने आरोप लगाया, श्री गांधी और उनकी पार्टी ने राफेल सौदे पर सर्वोच्च न्यायालय में तीसरे पक्ष की याचिका में अतिरिक्त रुचि ली, जो स्पष्ट रूप से संदिग्ध है। हो सकता है कि वे हमारी सुरक्षा की कीमत पर भारत के दुश्मनों की मदद के लिए ऐसा कर रहे हों। गांधी और उनकी टीम कुछ लोगों को रक्षा उपकरणों की खरीद में मदद करना चाहती थी, जिसकी जांच भी की जानी चाहिए।

योगी को काला झंडा दिखाने वाला युवक गिरफ्तार

प्रतापगढ़, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने का प्रयास करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। योगी शनिवार को प्रदेश ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के पिता भारत सिंह गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। मुख्यमंत्री का हेलीकाप्टर पुलिस लाइन में उतरा और जैसे उनका काफिला पुलिस लाइन के गेट से निकला वैसे ही फ्लीट के सामने पहुंच कर कथित रूप से समाजवादी पार्टी (सपा) कार्यकर्ता अरविंद यादव ने काला झंडा दिखाया।

युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : नीतीश

भागलपुर, (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के सुनहरे अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। कुमार ने यहां कौशल विकास व उद्यमिता एवं श्रम संसाधन विभाग के नियोजन सह- अप्रेंटिसशिप मेले का परिभ्रमण करने के बाद सभा को संबोधित करते हुये कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के सुनहरे अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रमंडलों एंव जिलों में लगाये जा रहे नियोजन मेले के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है।

वंशवाद, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है महागठबंधन : भाजपा

पटना, (एजेंसी)। बिहार भाजपा ने महागठबंधन में शामिल दलों पर बड़ा हमला करते हुए शनिवार को कहा कि इसके घटक कांग्रेस, राजद समेत अन्य सभी पार्टियां वंशवाद, परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं और विकास से इनका कोई लेना-देना नहीं है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष एवं उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय ने यहां कहा कि महागठबंधन में शामिल पार्टियों का विकास से इनका कोई लेना-देना नहीं है। इन दलों ने जवानों, किसानों एवं नौजवानों के साथ कार्यकाल के दौरान विश्वासघात किया है।

दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे मंजूरी की मांग

चंडीगढ़ी ,(एजेंसी)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रैस-वे परियोजना को अविलम्ब मंजूरी देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि कैप्टन सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इस संबंध में पत्र लिख कर उक्त प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया है। यह राजधानी को महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पंजाब में अमृतसर तथा जम्मू कश्मीर में कटरा को जोड़ने की केंद्र सरकार की ग्रीनफील्ड परियोजना का एक हिस्सा है।

कपड़ों से चार्ज होगा मोबाइल, पॉकेट में लगेगा सोलर पैनल

सेल्स दिखाई नहीं देंगी, कपड़े पहनते समय महसूस भी नहीं होंगी

नई दिल्ली ■ एजेंसी

जल्द आप अपने कपड़ों से अपना मोबाइल चार्ज कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये भला कैसे होगा तो हम बता दें कि वैज्ञानिक एक ऐसी पॉकेट बना रहे हैं जो कि चार्जिंग डॉक की तरह काम करेगी। यानी, इससे आप अपना मोबाइल फोन चार्ज कर पाएंगे। चार्जिंग डॉक से आप मोबाइल के अलावा फिटनेस ट्रैकर और टैबलेट भी चार्ज कर सकेंगे। इस पॉकेट में छोटे सोलर पैनल होंगे। यह पॉकेट आपके कपड़ों के फैब्रिक में बुना होगा। नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इनोवेशन पावर जेनरेट करने के तरीके को प्रमोट करेगा। साथ ही, इससे कॉर्बन का उत्सर्जन भी घटेगा। पैनल सिर्फ 3एमएम लंबा और 1.5एमएम चौड़ा होगा। इसे आसानी से फैब्रिक में सिला जा सकेगा। इस पॉकेट की मदद से लोग रास्ते चलते कहीं भी मोबाइल, फिटनेस ट्रैकर और टैबलेट चार्ज कर सकेंगे। इस नए इनोवेशन के बाद लोगों को पावर बैंक या प्लग सॉकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाने वाला फाइबर छोटी सेल्स के नेटवर्क से बना होगा और यह इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करेगा। इस एनर्जी से आप अपने डिवाइसेज चार्ज कर सकेंगे। ये सेल्स दिखाई नहीं देंगी। साथ ही, कपड़े पहनते समय यह महसूस भी नहीं होंगी। इस रिसर्च की अगुवाई करने वाले प्रोफेसर का कहना है, इस इनोवेशन से डिवाइसेज को सॉकेट में लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। साथ ही, कॉर्बन के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। रिसर्च टीम का कहना है कि कोई मोबाइल फोन या फिटनेस ट्रैकर चार्ज करने के लिए करीब 2,000 पैनल की जरूरत होगी। हालांकि, रिसर्च टीम ने अभी जो कॉन्सेप्ट मॉडल तैयार किया है, उसमें केवल 200 पैनल हैं।

पहला वैचारिक कुंभ बाबा विश्वनाथ की धरती पर संपन्न

कुंभ मानवता का सबसे बड़ा मिलन स्थल : योगी

अयोध्या ■ एजेंसी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कुम्भ मानवता का सबसे बड़ा मिलन स्थल है। श्री योगी ने शनिवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नवीन परिसर में समरसता कुंभ को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में कुंभ मानवता का सबसे बड़ा स्थल है जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में कुम्भ यह संदेश देता है कि धर्म और जाति का कोई भेदभाव नहीं है। पहला वैचारिक कुंभ बाबा विश्वनाथ की धरती पर सम्पन्न हुआ।

दूसरा कृष्ण की धरती मथुरा में आयोजित हुआ। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में तीसरा कुंभ का आयोजन हो रहा है जिसमें इस कुंभ से देश दुनिया को मानव कल्याण से जुड़ा हुआ यह संदेश दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौथा वैचारिक कुंभ लखनऊ और पांचवा वैचारिक कुंभ प्रयाग में सम्पन्न होना बाकी है। हमने इसके पहले राजधानी लखनऊ में कृषि कुम्भ का आयोजन किया था। कुम्भ का मतलब यह है कि भेदभाव नहीं होना चाहिये। सभी लोग बराबर हैं।

यह संदेश देने के लिये प्रदेश सरकार ने पांच स्थानों पर विभिन्न-विभिन्न विचारों से सम्बन्धित कुम्भों का आयोजन किया जिसमें पर्यावरण कुम्भ काशी में, नारी शक्ति कुम्भ वृदांवन में, समरसता कुम्भ अयोध्या में सम्पन्न हो रहा है। बाकी युवा कुम्भ लखनऊ और सांस्कृतिक कुम्भ प्रयागराज में सम्पन्न होगा। कुम्भ लगने से एक दूसरे का मिलन का सबसे बड़ा स्थल होता है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए श्री योगी ने कहा कि अब राजनीति करने वाले भी अपने को हिन्दू बताने लगे हैं जबकि यह सनातन धर्म की विजय है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी का नाम लेते हुए उन्होने कहा कि अब तो जनेऊ दिखा करके लोग गोत्र भी बताने लगे हैं।

कुंभ में देश-दुनिया को मानव कल्याण से जुड़ा संदेश दिया जा रहा

उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति को कोसा जा रहा है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिये। सनातन धर्म से वास्ता न रखने वाले शबरीमाला मंदिर में यह लोग जनभावनाओं का खिलाफत कर रहे हैं। श्री योगी ने कहा कि हमारे भारतीय संस्कृति में सनातन धर्मियों से बड़ा प्रकृति प्रेमी के लोग हैं जिसमें तुलसी, बरगद और पीपल की हम लोग पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्षो पहले हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर अक्षयवट का संरक्षण किया था और हमारा यही भारतीय संस्कृति भी है। इसी सबको संयोजने के लिये कुम्भ का आयोजन होता है।

गौशाला, पेड़, पक्षी हमारे देश की धरोहर, इनकी सुरक्षा करना धर्म

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में पहली बार सरयू तट पर आस्था का केन्द्र अक्षय वट का भी दर्शन कराया जाएगा। गौशाला, पेड़, पक्षी यह हमारे देश के धरोहर हैं। इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मनुष्य के साथ किये जाने वाला भेदभाव एक विकृति है। वेद के अधिकतर रचनायें दलितों के पूर्वजों ने किया है जैसे वाल्मीकि रामायण के रचियता महर्षि वाल्मीकि हैं लेकिन फिर उनके समाज से छुआछूत करते हैं। उन्होंने कहा कि दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। कुम्भ मेले को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम राहुल गांधी की तरह नया गोत्र बनाने लगे, जनेऊ दिखाने लगे तो दुर्गति तो होनी ही है। भारतीय समाज और संस्कृति में कभी छूआछूत और भेदभाव को महत्व नहीं दिया। उदाहरण देते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने भी कभी छुआछूत की भावना को नहीं माना। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की नगरी से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि कुम्भ पर्यावरण विरोधी नहीं हितैषी है। कुम्भ में जय श्री राम के नारे बराबर लगते रहे।

विक्रमसिंघे आज ले सकते हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ

कोलंबो ■ एजेंसी

श्रीलंका के विवादों में फंसे प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस पद से बर्खास्त किए गए रानिल विक्रमसिंघे के रविवार को दोबारा प्रधामंत्री पद की शपथ लेने की उम्मीद है। कोलंबो पेज की एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना बर्खास्त किए जा चुके प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को दोबारा इस पद पर नियुक्त करने के लिए कथिततौर पर तैयार हैं।

राष्ट्रपति ने शुक्रवार को उनसे फोन पर बातचीत की थी। विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नैशनल पार्टी (यूएनपी) ने कहा कि बातचीत के दौरान यह तय हुआ कि वह रविवार को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। दरअसल राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने एक विवादास्पद कदम के तहत 26 अक्टूबर को रानिल विक्रमसिंघे को हटाकर राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाया था, जिसके बाद देश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था।

26 अक्टूबर को रानिल विक्रमसिंघे को हटाकर राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाया था

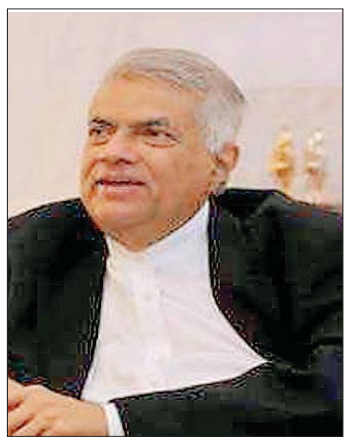

विक्रमसिंघे ने अपनी बर्खास्तगी को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। समाचार पत्र ने कहा कि नए मंत्रिमंडल को सोमवार को शपथ दिलाई जाएगी। इसमें श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के 6 सांसदों सहित कुल 30 सदस्य होंगे। राजपक्षे के बेटे नमाल राजपक्षे ने ट्वीट किया, देश में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे ने शुक्रवार राष्ट्र को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है।

फेसबुक बग की आयरलैंड की डेटा प्रॉटेक्शन संस्था ने शुरू की जांच

डबलिन,(एजेंसी)। आयरलैंड की डेटा प्रटेक्शन संस्था ने फेसबुक की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने स्वीकार किया है कि एक बग या तकनीकी खामी के कारण उसके 68 लाख उपयोगकर्ताओं के अकाउंट प्रभावित हुए। इसी के बाद शुक्रवार को यह जांच शुरू की गई।

आइरिश डेटा प्रटेक्शन कमिशन (डीपीसी) की जांच नए सख्त यूरोपीय निजता कानूनों के तहत होगी। ऐसी ही जांच अक्टूबर में भी की गई थी, जब फेसबुक ने 5 करोड़ यूजर्स के अकाउंट की सुरक्षा में सेंध लगने की बात स्वीकार की थी। संचार प्रमुख ग्राहम डॉयले ने कहा कि आइरिश डीपीसी को 25 मई 2018 को जनरल डेटा प्रॉटेक्शन रेग्युलेशन के आने के बाद से फेसबुक से सुरक्षा में सेंध लगने के कई नोटिफिकेशन मिले हैं। डीपीसी के पास फेसबुक की जांच करने का प्राथमिक यूरोपीय अधिकार प्राप्त है क्योंकि कैलिफॉर्निया स्थित सोशल नेटवर्किंग कंपनी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय डबलिन में है।

जीडीपीआर कानून नियामकों को निजी डेटा की सुरक्षा करने में नाकाम रही कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। इसका मतलब है कि दोषी पाए जाने पर फेसबुक पर 1.6 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि फेसबुक ने शुक्रवार को उस बग के लिए माफी मांगी, जिससे उपयोगकर्ताओं की ऐसी तस्वीरें भी सामने आ सकती थीं, जिन्हें उन्होंने कभी साझा नहीं किया। इस बग से थर्ड पार्टी ऐप्लिकेशन्स के जरिए 12 दिन के भीतर 68 लाख लोगों के अकाउंट प्रभावित हुए हैं।

गोमूत्र व गोबर बेचकर गौशालाओं की हालत सुधारेगी सरकार

गांधीनगर, (एजेंसी)। गुजरात सरकार गायों के कल्याण और उनके संरक्षण के लिए गोबर को आधार बना रही है। जीव दया के समर्थकों से प्रेरित होकर राज्य सरकार प्रदेश भर की पंजरपोल या पशुशालाओं में गोबर और गोमूत्र का भंडारण कर रही है। इसका मकसद पूंजी जुटाना है ताकि गोशालाओं में आश्रय लेने वाली लाखों लावारिस गायों व दूसरे पशुओं की देखभाल हो सके और उन्हें कसाईघरों में जाने से बचाया जा सके।

पशुशालाओं में भंडारण की होगी सुविधा, बेची जाएगी जैविक खाद

राज्य के वरिष्ठ मंत्री और गो संरक्षण मामलों के प्रभारी भूपेंद्र सिंह चुडास्मा कहते हैं, सरकार का इरादा है कि राज्य की पशुशालाओं में गोमूत्र और गोबर का भंडारण किया जाए। फिर इनका इस्तेमाल जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया जाए ताकि उनसे पूंजी जुटाई जा सके। सरकार इन पशुशालाओं में गोमूत्र और गोबर के भंडारण की सुविधा मुहैया कराएगी और बड़े स्तर पर खाद को बेचेगी।

सरकारी स्कूल टीचर बना महाठग 14 हजार लोगों को बनाया शिकार

हैदराबाद ■ एजेंसी

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर 14 हजार लोगों से ठगी करने का आरोप लगा है। पुलिस ने रविवार को आरोपी मेतुकु रविंदर को गिरफ्तार किया है। रविंदर ने ठगी के जरिए 158 करोड़ रुपए बनाए। उसका शिकार होने वालों में ज्यादातर किसान और मजदूर गांववाले ही हैं।

रविंदर अपने एक स्टूडेंट की बनाई कंपनी सन परिवार ग्रुप का सीईओ था और एक पोंजी स्कीम के जरिए उसने लोगों को ठगने की योजना बनाई थी। गुरुवार को जब एक पीड़ित हैदराबाद पुलिस के पास पहुंचा, तब इस घोटाले का खुलासा हुआ। पुलिस ने कंपनी के अलग-अलग बैंक अकाउंट में पड़े करीब 14 करोड़ रुपयों को सीज करने आदेश दिया है। पुलिस ने बताया कि रविंदर इस स्कीम के जरिए मिले पैसों से जमीनें खरीदता था और अपने एजेंट्स को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लाने पर फॉरेन ट्रिप का ऑफर देता था।

एजेंट्स को ज्यादा कस्टमर लाने पर फॉरेन ट्रिप का देता था ऑफर

टीचर से ऐसे बना महाठग साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा कि 42 वर्षीय रविंदर ने जनवरी में फर्म जॉइन की थी और स्कूल से छुट्टी ले ली थी। उन्होंने कहा, वह तेजी से आगे बढ़ना चाहता था इसलिए उसने एक फेक स्कीम लॉन्च की जिसमें लोगों को हर महीने 6 पर्सेंट रिटर्न देने का वादा किया। एक समय उसने 72 पर्सेंट तक रिटर्न दिया जिससे लोग उसके जाल में फंसते चले गए।

रविंदर सिद्दीपेट जिले के एक अपर प्राइमरी स्कूल में तेलुगु भाषा का टीचर था और जून महीने से लंबी छुट्टी पर था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, हमारी प्राथमिक जांच में सामने आया है कि वह इस साल जून महीने से लोगों को ठग रहा था।

जोरामथांगा विद्रोही से बने मुख्यमंत्री

एजल ,(एजेंसी)। मिजो नेशनल फ्रंट(एमएनएफ) के प्रमुख एवं विद्रोही से नेता बने जोरामथांगा शनिवार को पूर्वोत्तर में कांग्रेस शासित अंतिम राज्य मिजोरम के फिर से मुख्यमंत्री बने।

श्री जोरामथांगा का जन्म 13 जुलाई 1944 को सामथांग गांव में हुआ था। वह मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में दिसंबर 1998 से दिसंबर 2008 तक लगातार दो कार्यकाल तक रहे थे। मिजो नेशनल फ्रंट के अलगाव आंदोलन के दौरान लालदेंगा के बाद वह दूसरे पायदान पर थे और एमएनएफ को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलने के बाद में पार्टी नेता के रूप में उत्तराधिकारी बन गए। वह 1966 में मिजो स्वतंत्रता आंदोलन के शुरू होने पर इसके आंतरिक गतिविधियों में शामिल हुए और जंगल में चले गए। उन्हें रन बुंग इलाके के लिए सचिव बनाया गया जहां वह तीन सालों तक इस पद पर रहे। एमएनएफ के सभी कार्यकर्ता 1969 में पूर्वी पाकिस्तान चले गए। एमएनएफ के अध्यक्ष लालदेंगा ने उन्हें सचिव बना दिया। वह इस पद पर सात सालों तक रहे। श्री जोरामथांगा को 1979 में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गयी। सेना ने 1979 के विद्रोह के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन्हें असम राइफल्स क्वार्टर गार्ड में रखा था जिसके कारण वह असम राइफल्स को एजल शहर से बाहर रखने को लेकर लेकर सक्रिय थे।

वेदांता ग्रुप की कंपनी का स्टरलाइट का कॉपर प्लांट फिर खुलेगा

नई दिल्ली,(एजेंसी)। तूतीकोरिन स्थित वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टरलाइट के कॉपर प्लांट को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने निरस्त कर दिया है। इसके साथ तमिलनाडु पलूशन कंट्रोल बोर्ड को नया सहमति पत्र जारी करने का आदेश दिया है।

एनजीटी ने स्टरलाइट बंदी को अनुचित बताया है। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बेंच ने वेदांता लिमिटेड को अगले 3 साल में कल्याणकारी गतिविधियों पर 100 करोड़ खर्च करने को कहा है। सालाना 6 लाख टन कॉपर उत्पादन वाले प्लांट को मई में बंद किया गया था। स्टरलाइट कॉपर फैक्टरी को दोबारा खोलने पर फैसला करने के लिए एनजीटी ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसने राज्य सरकार के फैसले को गलत बताया था। मई में प्लांट के विरोध में भारी हिंसा हुई थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। तूतीकोरिन में प्लांट का विरोध कर रहे लोग 22 मई को जब पथराव और आगजनी का सहारा लेने लगे तो पुलिस ने फायरिंग कर दी जिसमें अब 13 लोगों की जान चली गई थी।

भारी हिंसा के बाद बंद हुआ था प्लांट

मई में प्लांट के विरोध में भारी हिंसा हुई थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। तूतीकोरिन में प्लांट का विरोध कर रहे लोग 22 मई को जब पथराव और आगजनी का सहारा लेने लगे तो पुलिस ने फायरिंग कर दी जिसमें अब 13 लोगों की जान चली गई थी।

सुविधा वॉटर मेट्रो से द्वीपों पर रहने वाले एक लाख लोगों को होगा फायदा

कोच्चि में चलेगी देश की पहली वॉटर मेट्रो

कोच्चि ■ एजेंसी

देश में जल्द ही आप वॉटर मेट्रो की भी सवारी कर सकेंगे। दिसंबर 2019 में यह सेवा शुरू हो सकती है। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने पहले इसे अप्रैल में चलाने की योजना बनाई थी लेकिन फिर इसे अक्टूबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया था।

819 करोड़ की आएगी लागत

यह प्रॉजेक्ट जर्मन की मदद से तैयार होगा। चरूरू के डायरेक्टर एपीएम मोहम्मद हैनिश ने बताया कि जनवरी तक मेट्रो का टेंडर दे दिया जाएगा।मेट्रो एजेंसी एक एंटिग्रेटेड वॉटर ट्रांसपॉर्ट प्रॉजेक्ट शुरू कर रही है जिसकी लागत 819 करोड़ होगी। जर्मनी की कंपनी केएफडब्ल्यू में 582 करोड़ रुपए लगा रही है। हैनिश ने कहा कि जर्मनी के राजदूत प्रॉजेक्ट की प्रगति से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, वॉटर स्टेशन तक पहुंचने के लिए बनाई जाने वाली सड़कों पर हमारा ध्यान है। पहले हम इन सड़कों को चौड़ी करेंगे। इससे द्वीपों पर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। वॉटर मेट्रो से द्वीपों पर रहने वाले करीब 1 लाख लोगों को फायदा होगा।

वर्तमान में योजना के अनुसार इस प्रॉजेक्ट में दो तरह की नाव होंगी। इन्हें फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक से बनाया जाएगा। ये नाव इको-फ्रेंडली होंगी और बैटरी से चलेंगी। केएमआरएल ने चार कंपनियों को नौकाएं बनाने का ठेका दिया है। ये नौकाएं एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक चलेंगी। 76 किलोमीटर की दूरी में 15 रूट पर नौकाएं चलाई जाएंगी।

इंडिगो फ्लाइट में बम की अफवाह एक घंटे की देरी के बाद भरी उड़ान

मुंबई,(एजेंसी)। इंडिगो के मुंबई से दिल्ली होकर लखनऊ जाने वाली फ्लाइट में बम रखे होने की खबर मिली, जिसके बाद शनिवार को उसे उड़ान भरने से रोक दिया गया। बम धमकी आकलन समिति ने इस खबर को गंभीरता से लिया।

एक महिला यात्री ने दी थी सूचना

विमान को खाली स्थान पर ले जाया गया। उन्होंने बताया कि बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने विमान को सुरक्षित घोषित कर दिया। इस घटना पर इंडिगो की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। विमान को सुबह छह बजकर पांच मिनट पर उड़ान भरनी थी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विमान में कितने यात्री सवार थे। हवाई अड्डे के एक सूत्र ने बताया कि गो एयर फ्लाइट जी8-329 से दिल्ली जा रही एक महिला यात्री टी-1 पर इंडिगो के चेक-इन काउंटर पर गई और वहां बताया कि इंडिगो की फ्लाइट 6ई 3612 में बम है।

महिला यात्री ने कुछ लोगों की तस्वीरें भी दिखाई और दावा किया कि वे राष्ट्र के लिए खतरा हैं। इसके बाद सीआईएसएफ के कर्मी उसे पूछताछ के लिए हवाई अड्डा पुलिस थाने लेकर गए। करीब एक घंटे की देरी के बाद विमान को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। सूत्रों का कहना है कि सीआईएसएफ के सहायक कमांडर के कार्यालय में बीटीएसी की बैठक बुलाई गई जिसमें धमकी को विशिष्ट बताया।

दखल

जलवायु परिवर्तनः संकल्पों में बाधाएं

पोलैंड के काटोविसे शहर में पर्यावरण बचाओ अभियान का वार्षिक आयोजन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन पर विश्व के 184 देश विचार-विमर्श कर रहे हैं, लेकिन विकसित और कुछ विकासशील देशों की जो मंशा है, उसे देखते हुए जलवायु परिवर्तन का लक्ष्य हासिल होता संभव होता नहीं दिख रहा है। जलवायु परिवर्तन ऐसा मुद्दा है, जिस पर जब तक सभी देश एक नहीं होंगे, हल नहीं मिलेगा।

विषैली हो रही जलवायु के संबंध में वर्ष 1995 से शुरू हुए पर्यावरण बचाओ अभियान का वार्षिक आयोजन आजकल पोलैंड के काटोविसे शहर में हो रहा है। जलवायु परिवर्तन पर विश्व के 184 देश विचार-विमर्श कर रहे हैं। पर्यावरण, जलवायु को मानवों के लिए स्वच्छ, निर्मल और निरोगी किस तरह बनाया जाए, इन्हीं चिंताओं को लेकर प्रति वर्ष जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पृथ्वी को चलाने वाले पंचतत्वों अर्थात् भू, नभ, जल, वायु व अग्नि के संतुलित उपयोग के लिए दुनिया के शासक और वैज्ञानिक वैचारिक स्तर पर तो सचेत हो चुके हैं, परंतु आवश्यकता निरंतर वास्तविक कार्य किए जाने की है। हालांकि इसके लिए भी प्रयास हो तो रहे हैं, पर कुछ देश अपने आर्थिक लाभ, भौतिक विकास और दूसरे लालचों के वशीभूत हो प्रकृति को विकृत कर रहे तत्वों पर नियंत्रण और प्रतिबंध के लिए सहमत नहीं हैं। वैश्विक तापमान में जीवनघातक वृद्धि को कम अथवा नियंत्रित करने के लिए पेरिस समझौते में हस्ताक्षर कर चुके कुछ देशों और हस्ताक्षर करने के बाद समझौते से हटने की हठ कर रहे अमेरिका के कारण पेरिस समझौते का महत्व व्यावहारिक रूप में कम होता जा रहा है।

जलवायु का शोधन करने के लिए पेरिस से पहले जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहे थे, वे वार्षिक औपचारिकताओं तक सीमित हो गए थे। इससे चिंतित कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों और मौसम विज्ञानियों के सुझावों पर जलवायु के प्रति संवेदनशील कुछ देशों ने एक समझौता किया, जो यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी यूएनएफसीसीसी के नाम से जाना जाता है। यूएनएफसीसीसी के सदस्य देशों में जितने भी विकसित, अर्द्ध-विकसित और विकासशील देश हैं, समझौते के अनुसार उनसे आशा की गई कि वे युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए 2020 तक अपने-अपने देशों में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाएं, इस व्यवहार को अपने देश और समाज का दैनिक व्यवहार बनाएं और इस हेतु वित्त व्यवस्था का दायित्व भी उठाएं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2015 में हुए इस समझौते को सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जिस पर नवंबर-2018 तक यूएनएफसीसीसी के 195 सदस्य देश हस्ताक्षर कर चुके हैं और 184 इसमें पक्षकार बन चुके हैं।

जो देश अपनी ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक और सामरिक जरूरतों के लिए कोयले की अधिक खपत कर बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, वे ही सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन भी करते हैं। दुनियाभर के कुल कार्बन उत्सर्जन में से चीन 29.4, अमेरिका 14.3, यूरोपीय यूनियन के देश 9.8, भारत 6.8, रूस 4.9, जापान 3.5 और बाकी देश 31.5 कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं। इसीलिए इन देशों से यह अपेक्षा है कि वे अधिक संवेदशनील बनें और अपने हिस्से के निर्धारित स्तर (2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस) तक वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने में योगदान दें, ताकि जलवायु को बिगड़ने से बचाया जा सके और वैश्विक ताप वृद्धि को सीमित या नियंत्रित किया जा सके। पेरिस संधि की परिणामोन्मुखी सफलता कार्बन उत्सर्जन में एकल रूप से अधिक भागीदारी करने वाले देशों चीन, अमेरिका, भारत, रूस, जापान और यूरोपीय संघ पर निर्भर करती है कि वे इसको साकार करने के प्रति वास्तव में कितने गंभीर हैं। वर्तमान में उनकी दिशा को देखते हुए तो यही लग रहा है कि वे कार्बन उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी कोयलाधारित कारखानों, निर्माणियों, उपक्रमों व उद्यमों को बंद करने व अपनी वैकासिक तथा उत्पादन आवश्यकताओं के लिए इनके पर्यावरणानुकूल विकल्प अपनाने के पक्ष में नहीं हैं।

पेरिस समझौते का दीर्घकालीन लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान में होनेवाली वृद्धि को पूर्व के औद्योगिक स्तर से दो डिग्री सेल्सियस नीचे रखने व वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का है, क्योंकि इससे जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और प्रभावों को वास्तव में कम किया जा सकता है। पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रत्येक देश को इस आशय का संकल्प, योजना और नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने होंगे कि वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने के लिए उसके द्वारा कितना योगदान दिया जा रहा है। हालांकि इसके लिए कोई विशेष क्रियाविधि अपनाने की बाध्यता नहीं, परंतु देशों को इस हेतु निर्धारित तिथि तक एक निश्चित लक्ष्य बनाना होगा और प्रत्येक नवीन लक्ष्य को पूर्व में प्राप्त किए गए लक्ष्य से जल्दी प्राप्त करना होगा। पर्यावरण में कार्बन का जो विष फैल चुका है और जिस कारण लाखों लोगों को अपने जीवन गंवाने पड़े, हजारों-लाखों अस्वस्थ हुए तथा श्वांस-दमा व अनेक अज्ञात रोगों की चपेट में आए, उस संबंध में वास्तविक चिंता बहुत कम देशों को है और जिनको है, वे इसके लिए अनेक निदान कर रहे हैं।

ऐसी ही चिंता से विचलित फ्रांस के पर्यावरण मंत्री निकोलस हुलॉट ने जुलाई-2017 में एक योजना की घोषणा की, जिसके तहत उन्होंने फ्रांस में 2040 तक पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों को प्रतिबंधित करने की बात रखी, जो पेरिस समझौता का प्रमुख हिस्सा थी। हुलॉट ने अपनी योजना में यह भी बताया कि उनका देश 2022 के बाद विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का प्रयोग कतई नहीं करेगा, लेकिन ऊर्जा कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए चार बिलियन का निवेश करेगा। पेरिस समझौते के उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नार्वे ने भी 2025 तक डीजल-पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। नीदरलैंड भी 2030 तक यही करेगा। इस उद्देश्य के लिए डच नेशनल रेल नेटवर्क पर चल रही विद्युत ट्रेनों को पहले ही पवन ऊर्जा द्वारा चलाया जाने लगा है। नीदरलैंड के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जून 2018 में विधेयक पारित किया था, जिसमें प्रस्ताव था कि नीदरलैंड 2050 तक 1990 के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन स्तर को 95 प्रतिशत तक कम करेगा, जो कि पेरिस समझौत के लक्ष्यों से काफी बड़ा लक्ष्य है।

यद्यपि एक ओर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कारकों को बंद करने के लिए कुछ देश उल्लेखनीय काम कर रहे हैं, तो अनेक शक्तिशाली देश और उनका अनुसरण करने वाले अन्य विकासशील देश निष्क्रिय बने हैं। इसी का दुष्परिणाम था जो जून 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को पेरिस समझौते से बाहर रखने की घोषणा की थी। उनका तर्क था कि विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के माध्यम से गरीब और विकासशील देशों की जैसी सहायता अमेरिका करता आया है, वह तब ही संभव हो पाया जब उसके उद्योगों को निर्बाध चलने दिया गया। अमेरिका सोचता है कि पेरिस समझौता जिन संकल्पित कार्यकारी बिंदुओं के बल पर कार्बन उत्सर्जन में कमी की मांग करता है, उस आधार पर उसे पारंपरिक उद्योगों को नियंत्रित, प्रतिबंधित और बंद करने से बहुत ज्यादा आर्थिक हानि होगी।

ऐसे में वह अंतरराष्ट्रीय मददगार और वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने वाले भागीदार का दोहरा दायित्व नहीं निभा सकता, लेकिन चूंकि हस्ताक्षर करने के बाद यदि कोई देश पेरिस समझौते से अलग होना चाहता है तो उसे हस्ताक्षर करने के उपरांत दो वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। अतः ट्रंप के कार्यकाल के समापन यानी नवंबर 2020 से पहले वह अवधि समाप्त हो जाएगी, जिसके बीतने पर अमेरिका इस समझौते से अलग हो जाएगा। अमेरिका ही नहीं, अपितु चीन और यूरोपीय संघ के कुछ देश भी पेरिस समझौते का अनुपालन करने में नियमों के विपरीत आचरण कर रहे हैं। यह ऐसा प्रश्न है जो पेरिस समझौते के जलवायु को प्राकृतिक बनाने के सिद्धांतों का भयावह विरोधाभास है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन में सुधार के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकेगा!

■ **विकेश कुमार बडोला**
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

राज-विचार

भाजपा में राफेल ने भरी ऊर्जा

राफेल डील मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में जुटे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने डील की जांच कराने से इंकार कर दिया है। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब भाजपा को हाल ही में पांच राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से निराश भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कामयाबी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट से 36 राफेल विमान सौदे में किसी तरह की जांच की संभावना को नकारते हुए कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8.7 बिलियन डॉलर की रक्षा डील में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं पाई है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे कहा जा सके कि सरकार ने किसी निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भाजपा को राहत तो देगा, मगर कांग्रेस के उस अभियान को भी कुंद करेगा, जिसके बहाने वह मोदी सरकार को भ्रष्ट बताने पर तुली थी। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब छह माह बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और बहुत जल्द देश भर की पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटने लगेंगी। भाजपा खेमे ने तो अभी से आक्रमक होने के संकेत दे दिए हैं। फैसला आने के बाद संसद में राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह के नारे लगे, वह बताते हैं कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को किस अंदाज में जवाब देने वाले हैं।

बता दें कि राफेल मामले में सबसे पहले वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 अक्टूबर को कहा था कि 10 दिनों के भीतर राफेल सौदे की पूरी प्रक्रिया की जानकारी मुहैया कराई जाए। फिर कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में राफेल विमानों की कीमत भी मांगी थी। एमएल शर्मा के बाद आठ अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और फिर 24 अक्टूबर को अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा के साथ संयुक्त रूप से प्रशांत भूषण ने इसी मसले पर याचिका दाखिल की थी। अब सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मोदी सरकार के लिए कोर्ट का यह फैसला बड़ी राहत है, खासकर तब जब करीब छह महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यह मामला अब और तूल पकड़ेगा, इसमें जरा सी भी गुंजाइश नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील को भ्रष्टाचार का उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री चोर है और चौकीदार चोर है का हैशटैग वॉर छेड़ दिया। देखते ही देखते, राफेल सौदा बोफोर्स डील की तरह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। गुजरात और कर्नाटक चुनावों में इसकी गूंज सुनाई दी। हालिया पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। भाजपा को मध्य प्रदेश, छग और राजस्थान की सत्ता गंवानी पड़ी। हालांकि, यह कहना मुश्किल है कि इस हार में राफेल मुद्दे का कितना बड़ा रोल था या कोई रोल था भी या नहीं।

दुष्कर्म पीड़िता की भी गरिमा

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को हाल ही एक सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि बलात्कार और यौन हिंसा पीड़ितों की पहचान किसी भी रूप में उजागर नहीं की जाए। कोर्ट का यह फैसला पीड़िताओं और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। मगर इससे कहीं ज्यादा जरूरी है, हम बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को होने ही न दें। यह संभव है, अगर हम थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं।

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को हाल ही एक सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि बलात्कार और यौन हिंसा पीड़ितों की पहचान किसी भी रूप में उजागर नहीं की जाए। फिर चाहे पीड़ित की मौत ही क्यों न हो चुकी हो। अदालत का इस बारे में साफ कहना था कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में बलात्कार पीड़ितों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न के उन मामलों जिनमें आरोपी अगर नाबालिग हों, वह इसकी भी प्राथमिकी सार्वजनिक नहीं करे। कोर्ट ने इस तरह के निर्देश ट्रायल अदालतों को भी देते हुए कहा कि वे फैसलों में पीड़ितों के नाम, पते और माता-पिता का नाम न लिखें। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेप पीड़िताओं के कल्याण और पुनर्वास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए और सरकारों से उस पर जल्द से जल्द अमल करने को भी कहा है।

अदालत ने सरकारों को निर्देश देते हुए कहा कि देश के प्रत्येक जिले में रेप पीड़िताओं के लिए 'एक वन स्टॉप सेंटर' बनना चाहिए। जहां रेप से संबंधित मुद्दों के समाधान होने के अलावा पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए भी उचित व्यवस्था हो। जाहिर है कि अदालत ने जो भी दिशा-निर्देश दिए हैं, वे दुष्कर्म पीड़िता को राहत प्रदान करने वाले हैं। इन निर्देशों से उसे भविष्य में न्याय मिलने में आसानी होगी और कहीं भी परेशानी पेश नहीं आएगी। गौरतलब है कि दिल्ली में निर्भया सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद से ही सर्वोच्च न्यायालय में बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा देने एवं उनके लिए पुनर्वास नीति और महिलाओं की सुरक्षा आदि से संबंधित छह अलग-अलग याचिकाओं की एक साथ सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत में दुष्कर्म पीड़िताओं की सुरक्षा से जुड़ा यह संवेदनशील मुद्दा उठाया गया था।

इस मामले में न्यायमित्र की भूमिका निभा रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी थी कि कोर्ट के विचाराधीन मामलों में मीडिया समानांतर सुनवाई कर रहा होता है। लिहाजा, शीर्ष अदालत को महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित करने चाहिए। इंदिरा जयसिंह का यह भी दावा था कि सक्षम अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने से पहले ही पुलिस, मीडिया को सूचनाएं लीक करती है, जो न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के समान है। उन्होंने कठुआ सामूहिक बलात्कार व हत्या मामले का जिक्र करते हुए यह दावा किया था कि इसमें अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने से पहले ही मीडिया ने कुछ आरोपियों के निर्दोष होने का फैसला भी सुना दिया था। जबकि आईपीसी की धारा 228-ए (यौन अपराध पीड़ित की पहचान उजागर करने से संबंधित) और पोक्सो कानून की धारा 23 इसकी साफ तौर पर मनाही करती है। एक तरह से देखें, तो अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की इन धाराओं की व्याख्या करने का अनुरोध किया था। जिस पर अदालत ने संजीदगी से विचार करते हुए दुष्कर्म पीड़िताओं की गरिमा का पूरा ख्याल रखा और इस संबंध में एक बार फिर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इसी मामले में पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया था कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रेस की आजादी और पीड़ित के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है।

किसी भी तरह का मामला हो, उसमें मीडिया के लिए एक लक्ष्मण रेखा बेहद जरूरी है। कहां से उसके अधिकार शुरू होते हैं और कहां पर खत्म। कहां तक उसकी आजादी है, और कहां पर ये आजादी खत्म। मीडिया मामले की कवरेज जरूर करे, पर इस बात का पूरा ख्याल करे कि उससे किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप न हो। जो भी रिपोर्टिंग हो, वह मीडिया एथिक्स के अनुकूल हो। रिपोर्टिंग ऐसी हो कि वह किसी की गरिमा के साथ कतई खिलवाड़ न करे। खास तौर से संवेदनशील मामलों में तो मीडियाकर्मियों का जैसे इम्तिहान होता है। दुष्कर्म मामलों की ही यदि बात करें, तो इन मामलों में जब तक आखिरी इंसाफ नहीं आ जाता, दुष्कर्म पीड़िता की पहचान किसी भी तरह से उजागर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसे मीडिया का अति उत्साह कहें, अज्ञानता कहें या फिर ज्यादा 'होशियारी', वे कई बार पीड़िता का नाम और पहचान तक उजागर कर देते हैं, जिससे पीड़िता की समाज में न सिर्फ बदनामी होती है, बल्कि आगे चलकर उसे इंसाफ पाने में भी दिक्कत पेश आती है। कई मामलों में तो मीडिया खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जांच एजंसी एवं जज की भूमिका में आ जाता है और खुद ही फैसला सुनाने लगता है, जबकि यह सब काम जांच एजंसियों और अदालत का है।

दुष्कर्म और यौन हिंसा जैसे संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग एहतियात व संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए। वरना अपराधी इसका फायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। अच्छी बात है कि अदालत ने इस संबंध में मीडिया को तो नसीहत दी ही, पुलिस और ट्रायल अदालतों को भी याद दिलाया कि वे किन कानून, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों से बंधे हुए हैं। वैसे, देखा जाए तो देश में बलात्कार अब घिनौना सच बनता जा रहा है। बलात्कार की शिकार युवती की पहचान उजागर न करने से कहीं ज्यादा जरूरी इस अपराध को खत्म किया जाए व इस अपराध की पहचान का हमेशा-हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए। पहचान छिपाने या उजागर करने से पीड़िता का दर्द कतई कम नहीं किया जा सकेगा। जब एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपने हालिया आंकड़े में बताता है कि 2014 से 2016 के बीच बच्चों के खिलाफ अपराधों मे 19.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है तो हम किसी बच्चे का नाम नहीं जानते, या याद नहीं रख पाते। केस, नंबर्स के तराजू में तौला जाता है। 2014 में बच्चों के साथ 89 हजार से ज्यादा क्राइम हुए और 2016 में एक लाख से अधिक। मगर इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज ने बलात्कार पर काबू पाने के लिए सरकार से अपेक्षा रखने के अलावा अपनी तरफ से क्या किया। बलात्कार की शिकार युवती से भेदभाव करने या उसके परिवार को समाज में जीने न देने के जतन करने के अलावा समाज ने सिर्फ व्यवस्था का मजाक उड़ाया और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए या नहीं, इस मुद्दे पर निरर्थक बहस की।

हम बेफिक्र और बेशर्म लोग हैं। सन्निपात में चिंघाड़ते, बड़बड़ाते पागल हो गए लोगों के लिए कोई ठोस सजा तय नहीं करते। कई बार उन्हें बचाने के लिए आंदोलन, जुलूस भी निकालते हैं। कठुआ इसका उदाहरण है। इसे सांप्रदायिक साजिश बताते हैं। धर्म पर धर्म चढ़ा जाता है तो जातियों पर जातियां। बदले लिए जाते हैं- खुद को बड़ा और असरदार साबित किया जाता है। कभी हम लड़कियों को कपड़े पहनने का सलीका सिखाने लगते हैं, तो कभी कुछ लोग रेप को लड़कों की भूल बताने लगते हैं। हम बलात्कार को इस तरह से लेते हैं, जैसे यह मनोरंजन का कोई जरिया हो। बातों में जितनी गंभीरता दिखती है, उससे आधी अगर करनी में दिख जाए, तो रेप करने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। अगर यह हो गया तो फिर न कोई पीड़ित होगी और न ही उसकी पहचान छिपाने की जरूरत पड़ेगी। निर्भया गैंगरेप के बाद कानून में जो बदलाव किए गए, फिर भी अगर बलात्कार नहीं थमा तो गलती किसी लड़की या बच्ची की नहीं है, बल्कि हमारी है। हम जाग तो रहे हैं, पर आंख बंद किए हैं। अगर आंखें खुली रखते तो क्या मजाल कोई हमारी बेटियों की तरफ देख ले।

■ **जाहिद खान**
(वरिष्ठ पत्रकार)

ट्विटर

राफेल डील के मुद्दे पर विपक्ष का झूठ सामने आ गया है। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सेना और देश की जनता से अपने किए की माफी मांगनी चाहिए।

अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष

झूठ बोलने वालों की हार हुई है। यह साबित हो गया है कि राफेल डील देश हित में हुई थी और केंद्र सरकार सारे काम देश हित में कर रही है। यह साबित हो गया।

अरुण जेटली, वित्त मंत्री

सत्यार्थ

ईश्वर पर विश्वास में ही सुरक्षा

एक बार उमर खय्याम अपने एक शिष्य के साथ किसी बीहड़ से गुजर रहे थे। नमाज पढ़ने का समय हुआ, तब दोनों ने ठीक-ठाक जगह देखनी शुरू कर दी। मगर तभी उन्हें कहीं दूर से आती शेर की आवाज सुनाई दी। उसे सुनकर शिष्य बेहद घबरा गया और तुरंत ही नजदीक के एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन उमर खय्याम तो खुद में ही डूबे थे। जैसे उन्होंने तो वह आवाज सुनी ही नहीं थी। वे एकाग्र होकर नमाज पढ़ने लगे। कुछ देर में शेर सचमुच ही वहां आ पहुंचा। लेकिन आश्चर्य कि वह कुछ देर वहां रुककर चुपचाप आगे भी निकल गया। शेर के चले जाने के बाद शिष्य पेड़ से नीचे उतर आया। फिर नमाज खत्म होने के बाद दोनों आगे चल पड़े। थोड़ी देर बाद जब खय्याम को एक मच्छर ने काटा, तो उसको मारने के लिए उन्होंने अपने गाल पर जोर से चपत लगा दी। यह देख वह शिष्य बोला-गुरुदेव अभी-अभी जब शेर आपके करीब आया था, तब आप बिलकुल नहीं घबराए, लेकिन एक छोटे से मच्छर द्वारा काटे जाने पर आपको इतना गुस्सा आ गया है कि आपने उसे मार दिया। तब उमर खय्याम ने उत्तर दिया- तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन यह भूल रहे हो कि जब शेर आया था, तब मैं खुदा के साथ था, जबकि मच्छर के काटे जाने के समय मैं एक इंसान के साथ हूं। यही तो वजह है कि मुझे शेर से डर नहीं लगा, जबकि मैं एक छोटे से मच्छर से घबरा गया। इंसान भगवान के साथ हो तो वह हमेशा सुरक्षित रहता है, जबकि मनुष्य के साथ उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब शिष्य की समझ में आ गया कि इंसान का भगवान के साथ होने का असली अर्थ क्या होता है। यह कि ईश्वर के साथ होने से इंसान की हिम्मत बढ़ जाती है।

■ **आरडी अग्रवाल 'प्रेमी'**

सार समाचार

स्ट्रासबर्ग में हमला करने वाले बंदूकधारी के परिवार के चार सदस्य रिहा: अभियोजक

पेरिस। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में लोकप्रिय क्रिसमस बाजार में गोलीबारी करने वाले बंदूकधारी के परिवार के चार सदस्यों को रविवार को हिरासत से रिहा कर दिया गया. पेरिस अभियोजक कार्यालय ने बताया कि हमलावर चेरिफ चेकत्त के तीन और करीबी लोग अब भी हिरासत में हैं. चेकत्त को पुलिस ने बृहस्पतिवार को मार गिराया था. कार्यालय ने बताया कि उसके माता-पिता और दो भाइयों को इस समय सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया है. फ्रांसीसी सुरक्षाबलों के 700 से अधिक कर्मी मंगलवार रात को हुए खूनखराबे के बाद से ही 29 वर्षीय चेकत्त की तलाश में थे. इस हमले में चार लोग मारे गए थे. फ्रांस के गृह मंत्री ने शुक्रवार को इस्लामिक स्टेट के उस दावे को खारिज कर दिया कि इस हमले के पीछे उसका हाथ है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या चेकत्त को यह हमला करने के लिए कोई मदद मिली. शनिवार शाम को प्रसारित हुए एक साक्षात्कार में चेकत्त के पिता ने कहा कि उनका बेटा आईएस का समर्थक बन गया था.

पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल डेविड हर्ले होंगे ऑस्ट्रेलिया के नए गवर्नर जनरल

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बलों के पूर्व प्रमुख को ब्रिटेन की महारानी के प्रतिनिधि के रूप में रविवार को अगला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया. हालांकि, अगले साल होने वाले महत्वपूर्ण प्रांतीय और संघीय चुनावों के बाद वह पदभार संभालेंगे. सेवानिवृत्त जनरल डेविड हर्ले (65) यह पद संभालने वाले रक्षा बल के दूसरे पूर्व प्रमुख होंगे. संवैधानिक राजशाही में यह कमोबेश सांकेतिक पद है, लेकिन सरकार में हस्तक्षेप करने की उन्हें शक्ति होती है. प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उन्होंने 'स्थिरता, निरंतरता और निश्चितता' सुनिश्चित करने के लिये हर्ले को चुना है. मॉरिसन ने कैनबरा में संवाददाताओं से कहा कि मेरे पास सिर्फ एक विकल्प था. मेरी पहली पसंद और वह मेरे बगल में खड़े हैं. उन्होंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो संवैधानिक भूमिका को पूरी गरिमा और समानता के साथ निभा सके. मॉरिसन अगले साल मई में संघीय चुनाव करा सकते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक आबादी वाले प्रांत न्यू साउथ वेल्स में मार्च में चुनाव हो सकते हैं. जनमत सर्वेक्षणों से ऐसा लग रहा है कि सत्तारूढ़ कंजरवेटिव गठबंधन को संघीय चुनाव में लेबर पार्टी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है. लेबर पार्टी ने हर्ले की नियुक्ति का स्वागत किया, लेकिन कहा कि पार्टी को प्रक्रिया के बारे में सूचित नहीं किया गया, जबकि राष्ट्रीय चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं.

पाकिस्तान: सरबजीत के हत्यारों के खिलाफ नहीं मिले सबूत, कोर्ट ने किया बरी

लाहौर- पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की 2013 में यहां कोट लखपत जेल में हत्या के मामले में दो प्रमुख संदिग्धों को उनके खिलाफ सबूत की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया. लाहौर सत्र अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाया जो कि पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित था. अदालत के एक अधिकारी के अनुसार लाहौर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद मोइन खोखर ने मुख्य संदिग्धों आमिर तांबा और मुदस्सर को सभी गवाहों के पलट जाने के बाद बरी कर दिया. अधिकारी ने कहा, 'एक भी गवाह ने अदालत में संदिग्धों के खिलाफ गवाही नहीं दी. अदालत ने उन्हें सबूत की कमी के चलते बरी कर दिया.' उन्होंने बताया कि दोनों संदिग्ध सुरक्षा कारणों से कोट लखपत जेल से एक वीडियो लिंक के जरिये अदालत में पेश हुए.

पीएम मोदी के कूटनीति के आगे फेल हुआ चीन, मालदीव ने कहा- 'सबसे पहले' भारत

नई दिल्ली (एजेंसी)।

मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह तीन दिन की राजकीय यात्रा पर रविवार को भारत पहुंचे. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने भारत आने पर सोलिह का स्वागत किया. सोलिह की राष्ट्रपति के रूप में किसी भी देश की पहली विदेश यात्रा है. सोलिह के साथ उनकी पत्नी फाजना अहमद और सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी उनकी यात्रा पर है. अपने भारत यात्रा पर सोलिह ने कहा कि मालदीव और भारत के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं. मालदीव के पास हमेशा 'भारत की पहली' नीति रही है.

मालदीव के विकास के लिए भारत ने निरंतर समर्थन और सहयोग किया है. सोलिह का यह बयान भारत और मालदीव के बीच संबंधों में एक नए उर्जा की तरह है. इससे पहले भारत और मालदीव के संबंध में जटिलता बनी हुई थी. पिछले सरकार में राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन ने 'भारत की पहली' नीति को उलटते हुए चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया था.

लेकिन इस बार मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद सोलिह की जीत के बाद भारत और मालदीव के संबंध एक बार फिर पटरी पर आते दिख रहे हैं. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 नवंबर को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे. प्रधानमंत्री मोदी इकलौते राष्ट्राध्यक्ष थे, जिन्हें इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया था.

आम चुनाव में सोलिह ने हासिल की थी जीत

पीएम नरेंद्र मोदी इससे पहले 2015 में मालदीव की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन वहां पर पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशिद की गिरफ्तारी के बाद बढ़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी. मालदीव में सितंबर 2018 में हुए आम चुनाव में मालदिवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के इब्राहिम मोहम्मद

सोलिह ने जीत हासिल की थी. उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हरा दिया था.

पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन माने जाते थे चीन के करीबी

भारत और मालदीव के संबंधों में पूर्ववर्ती यामीन के शासन के दौरान तनाव देखने को मिला था क्योंकि, उन्हें चीन का करीबी माना जाता है. भारतीयों के लिये कार्यवीजा पर पाबंदी लगाने और चीन के साथ नये मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर को लेकर भी भारत खुश नहीं था.

यामीन द्वारा इस साल पांच फरवरी को देश में आपातकाल की घोषणा किये जाने के बाद भारत और मालदीव के रिश्तों में और कड़वाहट आ गई थी. भारत ने इस फैसले की आलोचना करते हुए उनकी सरकार से लोकतंत्र और सियासी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को फिर से बहाल करने और राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग की थी. मालदीव में 45 दिन तक आपातकाल रहा था.

विक्रमसिंघे की पार्टी ने कहा, 'सिरिसेना के साथ दोबारा काम करने के लिए तैयार हैं'

कोलंबो। श्रीलंका के अपदस्थ प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूनएपी) ने कहा कि वह राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ काम करने के लिए तैयार है, जिन्हें उनकी सरकार के खिलाफ 'कुछ समूहों ने गुमराह' किया था. सिरिसेना ने विवादास्पद कदम उठाते हुए 26 अक्टूबर को विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया था और उनके स्थान पर महिंदा राजपक्षे को नियुक्त किया था, जिससे इस द्वीपीय देश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया था.

एक्सत् ज़ातिक पक्षय
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
UNITED NATIONAL PARTY

राजपक्षे ने उच्चतम न्यायालय के दो अहम फैसलों के बाद शनिवार को इस्तीफा दे दिया था, जिससे 69 वर्षीय विक्रमसिंघे की वापसी का रास्ता साफ हो गया. यूएनपी के उप नेता सजित प्रेमदास ने कहा कि उन्हें इस बात की हैरानी नहीं है कि राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को फिर से प्रधानमंत्री बनाने पर राजी हो गए जबकि पहले वह इस बात अड़े थे कि वह उन्हें नियुक्त नहीं करेंगे. कोलंबो गजट ने प्रेमदास के हवाले से कहा कि यह राष्ट्रपति के असली चरित्र को दिखाता है. प्रेमदास ने कहा कि यूनिटी सरकार के विरोधी कुछ समूहों ने राष्ट्रपति को गुमराह किया था और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने विक्रमसिंघे को हटा दिया था. उन्होंने कहा कि लेकिन अब सच सामने आ गया है. पार्टी सरकार में सिरिसेना के साथ दोबारा काम करने के लिए तैयार है. यूएनपी के महासचिव सांसद अकिला विराज करियावासम ने कहा कि नए मंत्रिमंडल का गठन दो दिन के भीतर किया जाएगा.

पाक सेना प्रमुख ने 15 आतंकवादियों की मौत की सजा की पुष्टि की

नई दिल्ली (एजेंसी)।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 ''आतंकवादियों'' को मिली मौत की सजा की रविवार को पुष्टि की। ये आतंकवादी नागरिकों की हत्या और पेशावर में साल 2016 में क्रिश्चियन कॉलोनी में आत्मघाती हमलों में शामिल थे। सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि जनरल बाजवा ने 15 आतंकवादियों को मिली मौत की सजा की पुष्टि कर दी जो आतंकवाद से संबंधित जघन्य अपराधों में शामिल थे।

बयान में कहा गया है कि आतंकवादियों को सशस्त्र बलों/कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर हमला करने, पेशावर के समीप क्रिश्चियन कॉलोनी पर हमले में शामिल आत्मघाती हमलावरों को उकसाने, शैक्षिक संस्थानों को तबाह करने तथा निर्दोष नागरिकों की हत्या के जुर्म में सजा दी गई। सितंबर 2016 में चार आत्मघाती हमलावरों ने पेशावर में क्रिश्चियन कॉलोनी में हमला कर दिया था। यह कॉलोनी सेना की छावनी के बाहर स्थित है। तालिबान के एक धड़े जमात-उर अहरार ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।

बयान में कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन के एक सदस्य इबरार ने पेशावर के समीप कॉलोनी पर हमला करने के लिए आत्मघाती हमलावरों को उकसाया और उन्हें हथियार, आत्मघाती जैकेट तथा वाहन उपलब्ध कराए। दोषियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उन्हें मौत की सजा दी गई। बयान में कहा गया कि दोषियों की आतंकवादी गतिविधियों के कारण 34 लोगों की मौत हुई। उनके पास से हथियार तथा विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई। मौत की सजा के अलावा 20 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई।

आलोचना के बाद वाशिंगटन के पास स्थित सैन्य कब्रिस्तान के दौरे पर पहुंचे ट्रंप

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुष्पचक्र चढ़ाने के कार्यक्रम के लिये वाशिंगटन के निकट स्थित एक सैन्य कब्रिस्तान के औचक दौरे पर पहुंचे। ट्रंप बारिश के बीच छाता लेकर 'अर्लिंग्टन नेशनल सेमेट्री' पहुंचे। उन्होंने 'वेटरन्स डे' (11 नवम्बर) पर यहां ना पहुंच पाने के लिये खेद भी प्रकट किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'फॉक्स न्यूज' को दिए साक्षात्कार में कहा, ''देश के लिए काम करने में मसरूफ था। मुझे यहां आना चाहिए था।'' ट्रंप ने पास में जमीन खरीदकर अर्लिंग्टन का विस्तार किए जाने की जानकारी भी दी। अभी यहां 4,00,000 पुरुष और महिलाएं दफन हैं। उन्होंने कहा, ''हम इस पर काम कर रहे हैं।''

ट्रंप के फ्रांस में एक सैन्य कब्रिस्तान पर नहीं जाने के लिए उनकी काफी आलोचना हुई थी। उस कब्रिस्तान में अमेरिकी सैनिक दफन हैं। ट्रंप प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में शिरकत करने के लिए पिछले महीने फ्रांस गए थे।

अयोध्या: महारानी हो के स्मारक का सौंदर्यीकरण और विस्तार का काम दो साल में हो सकता है पूरा

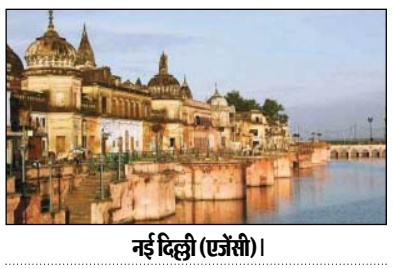

नई दिल्ली (एजेंसी)।

अयोध्या से कोरिया जाकर बसी पहली सदी की कोरियाई महारानी हो ह्वांग-ओक की याद में बने स्मारक को नए रंग-रूप में ढालने और उसके सौंदर्यीकरण का काम दो साल में पूरा होने की संभावना है. दक्षिण कोरियाई दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. अयोध्या में इस परियोजना की आधारशिला दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जुंग-सूक ने तब रखी थी जब वह बीते नवंबर में दीपोत्सव में शामिल होने के लिए इस पवित्र नगरी में आई थीं. कोरियाई दूतावास की सांस्कृतिक शाखा के अधिकारी ने बताया कि राम कथा पार्क के पास इस स्मारक के सौंदर्यीकरण में कोरियाई वास्तुकला से जुड़ी चीजें इस्तेमाल की जाएंगी. स्मारक को नए रंग-रूप में ढालने में करीब 25 करोड़ रुपये की लागत आएगी. उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा को बताया, ''स्मारक के डिजाइन का प्रस्ताव कोरियाई पक्ष की ओर से दिया गया और स्थानीय सरकार इस परियोजना को अमलीजामा पहनाएगी. इसके दो वर्षों में पूरे होने की संभावना है.'' कोरियाई दंतकथा के अनुसार, अयोध्या की राजकुमारी (राजकुमारी सूरीरत्ना) 48 ई. में कोरिया गईं और महाराज किम-सूरो से शादी की. कई कोरियाई नागरिक खुद को महारानी सूरीरत्ना का वंशज बताते हैं. उन्हें कोरिया में महारानी हौ ह्वांग-ओक के नाम से जाता है. बीते जुलाई में भारत और दक्षिण कोरिया की सरकारों ने राजकुमारी सूरीरत्ना की याद में बने स्मारक को नए रंग-रूप में ढालने और उसके विस्तार के लिए महारानी सूरीरत्ना स्मारक परियोजना संबंधी एक समझौते पर दस्तखत किए थे. दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला ने नवंबर में अपनी अयोध्या यात्रा की शुरुआत महारानी हौ के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करके की थी.

निकारागुआ पुलिस ने विपक्षी समाचार पत्र के कार्यालयों पर की छापेमारी, मानवाधिकार समूहों के परमिट रद्द

मनागुआ (एजेंसी)।

निकारगुआ पुलिस ने विपक्ष के समाचार पत्र के कार्यालयों पर छापेमारी की है. साथ ही कई मानवाधिकार एवं कार्यकर्ता समूहों के संचालन के परमिट भी रद्द कर दिए. पीड़ितों ने बताया कि नौ पुलिस अधिकारी कार्यालय में राइफलों के साथ शुक्रवार देर रात दाखिल हुए और लोगों को धक्का देना शुरू कर दिया. उन्होंने कुछ लोगों की पिटाई भी की और पत्रकारों का मजाक भी उड़ाया. पत्रकार कार्लोस फर्नांडो चामोरो के उन्हें उनके समाचार पत्र 'कॉन्फिडेन्शियल' और न्यूज चैनल 'एस्टा सेमाना' और एस्टा नोचे' के कार्यालयों पर बिना वारंट के छापेमारी करने की चुनौती देने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की.

चामोरो ने पत्रकारों से कहा, 'पुलिस के पास कोई वारंट नहीं था...इसलिए यह निजी संपत्ति, प्रेस की स्वतंत्रता और मुक्त उद्यम पर एक सशस्त्र हमला है.' छापेमारी के बाद 'कॉन्फिडेन्शियल' का मुख्य द्वार सील कर दिया गया. पुलिस ने कामकाज के उपकरण और दस्तावेज सील कर दिए. चामोरो ने पुलिस मुख्यालय जाकर उपकरण वापस देने की मांग की और कहा कि समाचार पत्र और टेलीविजन कार्यक्रम 'वाणिज्यिक रजिस्टर में पंजीकृत निजी कम्पनियां हैं, और उन संगठनों के साथ कुछ

लेना देना नहीं है जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है.'

मनागुआ में 'निकारागुअन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स' (सीईएनआईडीएच) और चार अन्य एनजीओ के कार्यालयों पर भी कब्जा कर लिया गया और सांसदों ने उनके संचालन के परमिट भी रद्द कर दिए.

जानिए कौन है नादिया मुराद, जिसने उठाई आईएसआईएस के जुल्म के खिलाफ आवाज

नई दिल्ली (एजेंसी)।

उत्तरी इराक में अपना बचपन गुजारने वाली यह लड़की आज 25 बरस की है. उसके जहन में उसकी जिंदगी के अब तक गुजरे तकरीबन 8125 दिनों की अच्छी बुरी यादें होनी चाहिए, लेकिन उसे याद है तो सिर्फ वह तीन महीने, जो उसने इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों की कैद में गुजारे. वह उन 90 दिनों की यातनाओं को याद करके सिहर उठती है और रूंधे गले से दुनिया से अपील करती है कि उसके जैसी बाकी लड़कियों के प्रति इस तरह बेपरवाह न रहें.

यजीदी समुदाय की है नादिया

हम बात कर रहे हैं नादिया मुराद की, जिन्हें हाल ही में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया. उन्हें यह पुरस्कार कांगो के एक स्त्री रोग विशेषज्ञ डेनिस मुकवेगे के साथ संयुक्त रूप से दिया गया. युद्धों अथवा सशस्त्र अभियानों के दौरान यौन हिंसा को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का पुरजोर विरोध करने वाली नादिया यजीदी समुदाय की हैं जो दुनिया के सबसे पुराने मजहबों में से एक माना जाता है.

बलात्कार के खिलाफ जागरुकता अभियान चलाती थी नादिया : उत्तरी इराक में सीरिया की सीमा से सटे शिंजा इलाके के पास कोचू गांव में अपने छह भाइयों और भरे पूरे परिवार के साथ रहने वाली नादिया मुराद ने बलात्कार के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस घिनौने लफ्ज की जलालत को पूरे तीन महीने तक अपने शरीर पर झेला. उन्हें शिकायत है कि वह तेल का जखीरा या हथियारों की खेप नहीं थीं, इसलिए अन्तरराष्ट्रीय समुदाय ने उन्हें चरमपंथियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया.

आईएस लड़ाकों ने कई लड़कियों को किया था अगवा : आईएस के लड़ाके अगस्त 2014 में नादिया के गांव में घुस आए और तमाम पुरूषों और बूढ़ी महिलाओं को मौत के घाट उतारने के बाद नादिया और उनके जैसी बहुत सी लड़कियों को बंधक बना लिया. उन्हें मोसुल ले जाया गया. नादिया को यह तक याद नहीं कि तीन महीने की कैद के दौरान उनके साथ कितने लोगों ने कितनी बार बलात्कार किया.

जर्मन सरकार की पहल से पहुंची जर्मनी

तीन महीने तक नरक से भी बदतर हालात में रहने के बाद एक दिन मौका मिलने पर अपनी जान हथेली पर लेकर चरमपंथियों के चंगुल से बदहवास भागी नादिया ने मोसुल की गलियों में एक मुस्लिम परिवार का दरवाज़ा खटखटाया और मदद की गुहार लगाई. उन्होंने नादिया की मदद की और उन्हें इराक के स्वायत्त क्षेत्र कुर्दिस्तान तक पहुंचा दिया. यहां वह शरणार्थी शिविर में रहीं और वहां से निकलने के लिए प्रयास करती रहीं. इसी दौरान जर्मन सरकार की पहल पर वह कुछ और लोगों के साथ जर्मनी पहुंचने में कामयाब रहीं.

मानवाधिकार मंच पर उठाई आईएस की बर्बरता के खिलाफ आवाज : इसके बाद उन्होंने आईएस के खिलाफ अपने स्तर पर जेहाद छेड़ा और उनकी कैद में रहने वाली महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकार के लिए हर मंच पर आवाज उठाई. बेशक नादिरा ने एक भयावह दौर देखा, लेकिन अपनी उस जिंदगी से विचलित हुए बगैर वो दिनरात उन महिलाओं के लिए काम में जुटी हुई हैं, जो आज भी यौन दासता का नरक भुगत रही हैं.

नादिया को मिला है नोबल पुरस्कार

नादिया ने 'द लास्ट गर्ल : माई स्टोरी ऑफ कैप्टिविटी एंड माई फाइट अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट' में रूह कंपा देने वाले जुल्मों की दास्तान लिखी है. नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते हुए नादिया ने इस बात की शिकायत की कि उन्हें और उनके जैसी लड़कियों को जेहादियों से मुक्त कराने के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुदाय ने कोई प्रयास नहीं किया. वह रूंधे गले से कहती हैं कि उनका वजूद तेल और हथियारों जैसे वाणिज्यिक हितों से कमतर रहा. वह चाहती हैं कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के बेपरवाह रवैए के खिलाफ अभियान चलाया जाए ताकि इस दुनिया को रहने की एक बेहतर जगह बनाया जा सके.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के राजनीतिक और निजी जीवन का लगभग हर पहलू जांच के दायरे में

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक और निजी जीवन का हर पहलू जांच के दायरे में है. ट्रंप व्हाइट हाउस, प्रचार अभियान और सत्ता हस्तांतरण से लेकर चैरिटी और कारोबार तक की जांच में उलझे हुए हैं. ट्रंप के कार्यकाल के दो साल से भी कम समय में उनके कारोबारी सहयोगियों, राजनीतिक सलाहकारों और परिवार के सदस्यों सभी की जांच की जा रही है. साथ ही उनके दिवंगत पिता के उद्योग की भी जांच-पड़ताल की जा रही है. ट्रंप प्रशासन में गृह मामलों के मंत्री रयान जिंके शुक्रवार को चौथे कैबिनेट मंत्री रहे जिन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की. पद पर रहते हुए उनके कार्यों को लेकर 17 मामलों की जांच चल रही है. ट्रंप के खिलाफ मामलों की जांच अगले साल रफ्तार पकड़ सकती है जब डेमोक्रेट्स का सदन पर नियंत्रण बढ़ने की संभावना है. हालांकि, ट्रंप ने इन जांचों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है और उनके ट्विटर अकाउंट पर आए दिन इसको लेकर उनका गुस्सा दिखाई देता है.

अपने कार्यकाल के लगभग आधे दौर में अब ट्रंप अपने अहम चुनावी वादों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. वह मैक्सिको के साथ लगती सीमा पर दीवार बनाने के लिए पांच अरब डॉलर चाहते हैं लेकिन रिपब्लिकन के नेतृत्व वाली कांग्रेस द्वारा यह धनराशि दिए बगैर ही उनका साल खत्म हो सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ चल रहे मामलों में रॉबर्ट मूलर जांच, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप, ट्रंप की कथित प्रेमिकाओं को धनराशि देने से जुड़े न्यूयॉर्क अभियान-वित्त मामला और ट्रंप की उद्घाटन समिति के वित्त और कार्यों की जांच चल रही है. ये जांच राष्ट्रपति, ट्रंप के परिवार और उनके कारोबारी हितों के लिए खतरा हैं. डेमोक्रेट्स के सदन पर नियंत्रण के बाद यह खतरा और बढ़ेगा ही. वे खुद से जांच शुरू कर सकते हैं और महाभियोग लाने पर भी विचार कर सकते हैं. अगर ट्रंप महाभियोग से बच भी जाते हैं तो डेमोक्रेट्स की जांच उनके लिए सिरदर्द बनेगी.

विश्व हिंदू परिषद के विराट धर्म सभा में उमड़ा जन सैलाब

जय श्री राम के जयघोष से गूंजा शहर

संतों ने मंदिर निर्माण की दिखाई कटिबद्धता

सूरत। विश्व हिन्दू परिषद की और से रविवार को शहर के लिंबायत क्षेत्र में विराट धर्म सभा का आयोजन किया गया। नीलगिरी सर्कल के निकट विशाल मैदान में आयोजित इस सभा में लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए धर्मसभा की तैयारी परिषद की और से पिछले एक सप्ताह से का जा रही थी। जिसमें सूरत शहर के कोने-कोने से आए रामभक्तों के साथ बड़ीं संख्या में साधु संतों तथा महेतों ने भाग लिया। इस अवसर पर सारा शहर भगवा रंग में रंगा नजर आया। राम भ्भक्तों द्वारा जय श्री राम का जयघोष किया गया। जिसकी गूंज से सारा शहर राममय हो गया। सभा में उपस्थित संतो ने उपस्थित जनसमूदाय का अह्वान करते है मंदिर निर्माण के प्रति अपनी कटिबद्धता का परिचय दिया। संतों ने रामभक्तों से कहा कि राममंदिर का निर्माण अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा।

उन्होंने भाजपा सरकार की मंशा पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि जो सरकार राम के नाम पर सत्ता में आई वहीं सत्ता पाने के बाद र ाम को भूल गई। भगवान श्रीराम देश के करोड़ों हिन्दुओं के आराध्य है जो पिछले 26 वर्षों से टेंट में है। जो हिन्दू अपने आराध्य को सम्मान नहीं दिला सकते उन्हें हिन्दू कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। संतों ने अह्वान किया कि जिस प्रकार एक झटके में हिन्दुओं ने बाबरी के कलंक को मिटाया था उसी प्रकार एक बार और जोर लगाने की आवश्यकता है। भाजपा सरकार यदि राममंदिर के लिए उचित पहल नहीं करेगी तो करोड़ों हिन्दूओं को ही अपने आराध्य को उचित स्थान दिलाना पडेगा। धर्मसभा में विश्व के सभी धर्मों के इतिहास की बात करते हुए संतों ने कहा कि हिन्दु धर्म सत्यसनातन धर्म हो जो विश्व का सबसे पुराना धर्म है। कलान्तर में हिन्दु धर्म में ऊंच,नीच, जाति-पात तथा छुआछुत की दुष्प्रकृति के चलते हिन्दु धर्म कई खेमों में बट गया। जिसका आततायियों ने फायदा उठाया। आपसी फूट के कारण कमजोर हो चुके हिन्दू धर्म पर लगातार हमले हुए। हिन्दू धर्म और संस्कृति को नष्ट करने के लिए हिन्दू मंदिरों पर हमले किए गए। उन्हे तहस नहस किया गया। मंदिर के मलवे से मस्जिद बनाया गया इसी कड़ी में अयोध्या में भी श्रीराम जन्म भूमि स्थली को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया। हिन्दू समाज न तो उस समय कमजोर था और न ही अब कमजोर है परन्तु फिर भी हजारों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। इसका मात्र एक ही कारण था आपसी फूट जिसका विदेशी आक्राताओं ने नाजायज लाभ उठाया।

अब समय आ गया है कि हिन्दू अपने गौरव की स्थापना के लिए निंद से जाग कर मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म रक्षित रक्षित: अर्थात धर्म की रक्षा के बिना धर्मालंबियों का कल्याण संभव नहीं है। अयोध्या मे जब तक भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक देश के साधु संत चैन से नहीं बैठेंगे। इस दौरान संतो द्वारा मंदिर निर्माण के लिए लाए गए ईंटों की प्राण प्रतिष्ठा की गई तथा सभी राम भ्भक्तों को श्रीराम मंदिर के भव्य निर्माण में सहभागी होने को कहा गया। निलगिरी के विशाल मैदान में होने वाले विराट धर्मसभा में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो इसके लिए समूचित व्यवस्था की गई थी। कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी।

सूरत। सूरत महानगर पालिका द्वार हो रहे इस बांधकाम को प्लान के साथ में मंजूर किया गया है इस मंजूर प्लान में जो सारे काम काज हो रहे है क्या इस बात की जांच सूरत महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा की जा रही है या नहीं?

रंगे हाथ पकड़े गए 3 चोर 15,95 लाख का मोबाईल बरामद

सूरत। शहर में जैसे जैसे ठंड का माहौल बाव पसार रहा है वैस वैसे चोरी की घटनाएं बढती जा रही है। जिसकों ध्यान में रखते हुए कतारगाम पुलिस ने रात्रि में गस्त बढ़ा दिया है। जिसके परिणाम स्वरूप फूलपाड़ा रोड़ पर भाटिया मोबाईल नामक दुकान में चोरी कर रहे तीन चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कतारगाम के फुलपाड़ा रोड़ स्थित राज शांपिंग सेंटर में स्थित भाटिया मोबाईल नामक दुकान का शटर तोड़कर 95 मोबाईल चुराकर चोर भाग रहे थे। तभी डी स्टाफ ने शंका के आशार पर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। जिसके कब्जे से 95 मोबाईल बरामद हुआ। पुछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने राज शांपिंग सेंटर की एक दुकान से मोबाईल चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने दुकान के मालिक मुकेश केशव हिसरा, निवासी गुणातीत नगर, कतारगाम से फरियाद लेकर 15,95 लाख कीमत के 95 मोबाईल की चोरी का माला र्द कर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु कर दी है। मोबाईल चोरी की घटना में शामिल आरोपियों की जांच में पाया गया कि तीनों नाबालिग उम्र के है। जिसके चलते उन्हें जुवेनाइल एक्ट के तहत तीनों पर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कतारगाम जी.आई.डी.सी विस्तार में स्थित भाटिया मोबाईल शाप में शुक्रवार की देर रात मोबाईल की दुकान में चोरी करने के लिए 5 लोग आए थे। जिसमें से 2 लोग दुकान का शटर तोडकर अंदर घुसकर चोरी कर रहे थे। जबकि उनमें से 3 लोग दुकान के बाहर थे। इसी बीच पेट्रोलिंग कर रही पुलिस अचानक घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस को देखर दुकान के बाहर खड़े तीनों चोर भागने लगे। जिसके बाद पुलिस ने दुकान को बाहर से बंद कर दिया जिससे अंदर घुसे चोर बाहर नहीं निकल सके। पेट्रोलिंग पर आई पुलिस ने भाग रहे तीनों चोरों का पीछा किया जिसमें से 2 भागने में कामयाब रहे। जबकि तीसरे चोर को भागते समय गिर जाने से घायल हो गया जिसे पुलिस ने धर दबोचा। घायल को पुलिस ने पकड़ कर इलाज के लिए हास्पिटल में भर्ती कराया। पुलिस ने दुकान में बंद अन्य दो चोरों को भी पकड़ लिया।

3.85 करोड़ रुपये के पुराने नोटों के साथ रांदेर पुलिस ने एक को पकड़ा। रांदेर पुलिस स्टेशन में नोटों को गिनती पुलिस।

सूरत। जनहित सेवा समिति द्वारा रविवार को उधना रेल्वे स्टेशन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)